आकाशवाणी केन्द्र शिमला
21.02.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

मादक पदार्थ

राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी से निपटने के लिए सख्त कानून लागू कर, समन्वित कार्रवाई और जन सहभागिता के माध्यम से प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि पुलिस विभाग ने विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त कर अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है और एनडीपीएस एक्ट व पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम पेश करने की भी योजना बना रही है, ताकि कानूनी प्रावधानों को मजबूत किया जा सके।

रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगी। वे आज शिमला में यूनेस्को के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार शिक्षा प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाएगी और जल्द ही यूनेस्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूनेस्को के साथ दीर्घकालिक साझेदारी इन प्रयासों को और मज़बूत करेगी।

मुख्य सचिव

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित की गई। बैठक में आपदा के दौरान संचार के लिए इस्तेमाल होने वाले हैम रेडियो के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रदेश में अब तक 88 कर्मचारियों को हैम रेडियो का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस दौरान मुख्य सचिव ने लाहौल–स्पिति और किन्नौर के उपायुक्तों को डॉप्लर राडार स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए।

एचआरटीसी

एच.आर.टी.सी. चालक परिचालक यूनियन ने रात्रि भत्ते सहित अन्य वित्तीय लाभ न मिलने पर सरकार व प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों यूनियनों ने शिमला स्थित निगम मुख्यालय के बाहर धरना–प्रदर्शन किया और 15 दिन के भीतर सभी लंबित लाभ देने की मांग की। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बार–बार झूठ बोलकर वित्तीय लाभ देने की तिथि आगे बढ़ा रहे हैं और समय पर वित्तीय लाभ नहीं दिए गए, तो 6 मार्च से चालक काम छोड़ों अभियान छेड़ेंगे।

एसएमसी शिक्षक

प्रदेश में मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले एस.एम.सी. शिक्षक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। शिमला के चौड़ा मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एसएमसी शिक्षकों का कहना है कि वे नियमितीकरण की नोटिफिकेशन के बाद ही स्कूलों में लौटेंगे। शिक्षकों का कहना हैं कि वे करीब 12 सालों से नियमितीकरण की राह देख रहे हैं और सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। एसएमसी शिक्षक संघ के प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा कि एसएमसी शिक्षक दूरदराज क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं और दो सौ के करीब स्कूल इन शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के दस हजार पद खाली हैं और सरकार की मंशा एस.एम.सी. शिक्षकों को नियमित करने की नहीं है।